एयर इंडिया के बाद छह और कंपनियों में विनिवेश होगा

योजना

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान ब्यूरो

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। एयर इंडिया की बिक्री के बाद लक्ष्य पटरी पर आता हुआ दिख रहा है। एयर इंडिया के बाद सरकार ने आईडीबीआई बैंक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम के निजीकरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। जबकि बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। एलआईसी के आईपीओ से 10 फीसदी हिस्सेदारी अगले साल मार्च तक बेचे जाने की तैयारी अंतिम चरणों में है।

3.5 लाख करोड़ रुपये जुटा चुकी है सरकार छह साल में विनिवेश से

1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में

80 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये तक एलआईसी में विनिवेश से

26 हजार करोड़ रुपये जुटा पाई है सरकार अभी चालू वित्त वर्ष में

18 हजार करोड़ रुपये अकेले एयर इंडिया की बिक्री से मिले हैं

एलआईसी से सबसे अधिक उम्मीद

सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का विनिवेश इस वित्त वर्ष के अंत यानी मार्च 2022 तक करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए एलआईसी का आईपीओ लाने की तैयारी है जिसके लिए मर्चेंट बैंकर नियुक्त किए जा चुके हैं। एलआईसी का मूल्यांकन आठ से 10 लाख करोड़ रुपये होने की अनुमान है। ऐसा होने पर सरकार इसकी 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 80 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटा सकती है।

आईडीबीआई बैंक

इस बैंक में केंद्र सरकार और और एलआईसी की कुल मिलाकर 94 फीसदी हिस्सेदारी है। एलआईसी की 49.24 फीसदी और सरकार की 45.48 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा 5.29 फीसदी हिस्सेदारी अन्य की है।

एससीआई-पवन हंस

शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का निजीकरण मार्च 2022 से पहले किया जाना है। सरकार 63.75% हिस्सेदारी बेच रही है। वहीं पवन हंस में 51% हिस्सेदारी है और 49% हिस्सेदारी सरकारी तेल एवं गैस कंपनी ओएनजीसी की है।

नीलांचल इस्पात और बीईएमएल

नीलांचल इस्पात निगम और बीईएमएल का भी निजीकरण मार्च 2022 तक किया जाना है। नीलांचल इस्पात निगम में केंद्र सरकार की कई कंपनियों एमएमटीसी, एनएमडीसी, बीएचईएल, एमईसीओएन और ओडिशा सरकार की दो कंपनियों ओएमसी और आईपीसीओएल का संयुक्त उद्यम है। वहीं बीईएमएल में सरकार अपनी 54.03% हिस्सेदारी में से सिर्फ 26 फीसदी बेचना चाहती है।